



- दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से फरारगंज तहसील में 'प्रशासन आपके द्वार' के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया।
- ज़ोनल मत्स्य अधिकारी ने पंजीकरण रद्द करने हेतु प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाजों की एक सूची जारी की।
- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष ने मध्योत्तर अंडमान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मुद्दा उठाया।
- नॉर्थ बे में कल अस्मिता साइक्लिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा।



दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से फरारगंज तहसील में सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव एस की अध्यक्षता में 'प्रशासन आपके द्वार' पहल के तहत राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसील के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। शिविर के दौरान सुनवाई और आवेदनों की जांच के पश्चात, भूमि से संबंधित 65 डायवर्जन मामलों का निपटारा किया गया। प्रशासन ने कहा कि सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित समाधान और प्रशासनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पूरे जिले में इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे।



दक्षिण अंडमान स्थित ज़ोनल मत्स्य अधिकारी ने उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन और संबंधित जहाजों की वर्तमान भौतिक स्थिति के मूल्यांकन के बाद, पंजीकरण रद्द करने के लिए प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाजों की एक सूची तैयार की है। प्रस्तावित जहाजों की सूची अंडमान निकोबार प्रशासन के अलावा मत्स्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहाज मालिकों, ऑपरेटरों व अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए ज़ोनल मत्स्य कार्यालय तथा जंगलीघाट स्थित फिश लैंडिंग सेंटर की सूचना पट्ट पर भी सूची प्रदर्शित की गई है।

यदि किसी व्यक्ति को इस सूची में शामिल किसी भी जहाज के संबंध में कोई आपत्ति, दावा या प्रासंगिक जानकारी देनी है, तो वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने सहायक दस्तावेजों के साथ ज़ोनल मत्स्य कार्यालय में एक अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं।



पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर "12 साल – विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" नाम से विशेष श्रृंखला में आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पिछले 12 वर्षों में, केन्द्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए, चार करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, देशभर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जरूरतमंद परिवारों को पांच लाख रुपये तक का, स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को, ऋण देने के लिये शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत, अब तक एक करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं।



12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसायटी ने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, स्ट्रेट आइलैंड में ग्रेट अंडमानी जनजाति के सदस्यों के लिए एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग के अभ्यास के माध्यम से जनजातीय समुदाय के बीच समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। इस विशेष सत्र में ग्रेट अंडमानी जनजाति के प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों, प्राणायाम और विश्राम तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई।



अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मध्योत्तर अंडमान के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

दौरे के दौरान, उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रंगत के सहायक आयुक्त से मुलाकात की और तत्काल राहत उपायों, पुनर्वास प्रयासों और बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता देने पर चर्चा की।



भारत सरकार की अस्मिता पहल के तहत नॉर्थ बे में कल अस्मिता साइक्लिंग लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता सुबह 7 बजे आरंभ होगी। प्रतिभागियों से सुबह साढ़े छः बजे तक उपस्थित रहने को कहा गया है। इस वर्ष यह लीग द्वीपसमूह के तीनों जिलों में आयोजित किया जा रहा है। विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता सभी के लिए निःशुल्क है।



नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान के ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। दक्षिण अंडमान के गुप्तापाड़ा और सीडीपीओ कार्यालय (डिगलीपुर) में आज शिविर जारी है। क्षेत्र में 17 से 19 को भी शिविर लगेगा। इसके अलावा हरमिन्दर बे में कल, हम्फ्रीगंज में 16 और 17 जून को, वंडूर तथा नील केन्द्र में 18 और 19, टुश्नाबाद में 22 और 23, कोलीनपुर में 24 और 25, को शिविर के आयोजन किए जाएंगे। इन विशेष शिविरों के दौरान नागरिकों से आधार से जुड़े कार्यों को पूरा करने को कहा गया है।



मत्स्य पालन विभाग केंद्रशासित प्रदेश योजना के तहत मछुआरों के लिए सब्सिडी कार्यक्रम 'मत्स्य पालन इनपुट की आपूर्ति – आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं' लागू कर रहा है। गैर-जनजातीय श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और जनजातीय श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को द्वीपसमूह का मछुआरा या जनजाति, उनके पास पंजीकृत गैर-मोटरीकृत या मोटरीकृत मछली पकड़ने वाली नाव, साथ ही वर्तमान वर्ष सहित लगातार दो वर्षों का वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए वर्ष 2026–27 के दौरान आवश्यक मत्स्य पालन आवश्यकताएं खरीदने के इच्छुक नगरपालिका और जनजातीय क्षेत्रों के मछुआरों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आवेदन फॉर्म और विस्तृत नियम व शर्तें मत्स्य पालन निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों और नजदीकी मत्स्य उप-केंद्रों से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन 30 जून तक मत्स्य क्षेत्रीय कार्यालय या उप-केंद्र में जमा किए जा सकते हैं।



जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में सत्र 2026–27 में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार प्रवेश के लिए सामान्य कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं।



कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि धान की उन्नत किस्मों के बीज द्वीपों के सभी कृषि उप-डिपो पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पारंपरिक धान की किस्मों के बीज निंबुडेरा स्थित गुणन फार्म में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि उप-डिपो, क्षेत्रीय कृषि कार्यालय या किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

